

## झारखण्ड गजट

# असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 1 राँची, बुधवार,

2 जनवरी, 2019 (ई॰)

#### श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

संकल्प

21 दिसम्बर, 2018

संख्या:-2/एम॰ डब्लू॰-204/2012-श्र॰नि॰-2365-- चूँकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण/पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद का पुनर्गठन राज्य सरकार आवश्यक समझती है।

अतएव राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 के द्वारा प्रदत शिक्तयों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद का गठन करते हुए है, जिसमें निम्निलिखित सदस्य होंगे :-

#### स्वतंत्र सदस्य

1.	सचिव/प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,झारखण्ड, राँची	- अध्यक्ष
2.	श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची	- सचिव-सह-संयोजक
3.	निदेशक, न्यूनतम मजदूरी झारखण्ड, राँची	- सदस्य
4.	ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के एक प्रतिनिधि	- सदस्य
5.	जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के एक प्रतिनिधि	- सदस्य
6.	अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड	- सदस्य
7.	ज़ेवियर इंस्टीच्युट ऑफ सोशल साईंसेज, राँची के एक प्रतिनिधि	- सदस्य

#### नियोजकों के प्रतिनिधि

1.	अध्यक्ष/सचिव, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एम-5,	
	आदित्यपुर, कांडरा रोड़, आदित्यपुर	-सदस्य
2.	अध्यक्ष/सचिव,झारखण्ड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, राँची	- सदस्य
3.	अध्यक्ष/सचिव,संथाल परगना, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, दुमका	- सदस्य
4.	अध्यक्ष/सचिव, छोटानागपुर होटल एवं रेस्तरा एसोसिएशन,राँची	- सदस्य
5.	कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य	- सदस्य
6.	प्राचार्य, डी॰ पी॰ एस॰, सेटलाइट कॉलोनी, सेल, राँची	-सदस्य
7.	राज हॉस्पिटल, मेन रोड़, राँची	- सदस्य
8.	सचिव, रामकृष्ण मिशन, देवघर	- सदस्य
9.	बीड़ी मर्चेन्ट एसोसिएशन, चकरधरपुर एक प्रतिनिधि	- सदस्य
10	. अध्यक्ष/ महामंत्री भारतीय किसान संघ झारखण्ड के एक प्रतिनिधि	- सदस्य
11	. रिफेक्ट्रीज ऑनर्स एसोसिएशन, धनबाद एक प्रतिनिधि	- सदस्य
12	. एम॰डी॰ टाटा स्टील या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	- सदस्य
13	. अध्यक्ष/सचिव,झारखण्ड प्रदेश ईंट निर्माता संघ,	
	दुर्गा मन्दिर के सामने कांके रोड़ राँची	- सदस्य

#### नियोजितों के प्रतिनिधि

1.	ऑल इण्डिया सेंट्रल कौंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन (AICCTU), झारखण्ड एक प्रतिनिधि	थे - सदस्य
2.	ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन सेंटर (AIUTUC), झारखण्ड एक प्रतिनिधि	- सदस्य
3.	ऑल इण्डिया यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (AIUTUC), झारखण्ड एक प्रतिनिधि	- सदस्य
4.	भारतीय मजदूर संघ (BMS), झारखण्ड एक प्रतिनिधि	- सदस्य
5.	सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (CITU), झारखण्ड एक प्रतिनिधि	- सदस्य
6.	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC), झारखण्ड एक प्रतिनिधि	- सदस्य
7.	यू॰टी॰यू॰ सी॰ लेनिन सारणी, झारखण्ड एक प्रतिनिधि	- सदस्य

(परिवर्तित ट्रेड यूनियन-ए॰आई॰यू॰सी॰, राज्य कमिटी बी॰-61, सेक्टर-2, धुर्वा, रांची)

8. झारखण्ड बीड़ी मजदूर संघ एक प्रतिनिधि

- सदस्य
- 9. अध्यक्ष/सचिव, सिंहभूम असंगठितकामगार यूनियन, क्रॉस रोड़ नं०-07 क्वाटर नं०-3, पो०-एग्रीको, जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम एक प्रतिनिधि

- सदस्य

- 10. श्री गिरिजा शंकर ओझा, ब्यूरो प्रमुख, ए॰एन॰ आई॰ राँची, दुकान नं॰-27, फिरायालाल के सामने फिरायालाल चौक, मेन रोड, राँची-सदस्य
- 11. भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कामगार यूनियन-

वनस्थली निवास, ग्राम-मांझीलाडीह, विराट्प्र, धनबाद

- सदस्य

12. झारखण्ड घरेलू कामगार यूनियन, पूर्वा इंक्लेव हैदर अली रोड कोकर, राँची

- सदस्य

13. अध्यक्ष/सचिव,झारखण्ड असंगठित दैनिक मजदूर संघ देवघर

- सदस्य

- 2. नवगठित समिति(पर्षद) का मुख्यालय, राँची रहेगा।
- 3. नवगठित समिति(पर्षद) की अवधि दो वर्षों की होगी, परन्तु दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अगला पुनर्गठन होने तक उक्त समिति (पर्षद) कार्य करती रहेगी।
- 4. चूँिक यह समिति (पर्षद) वैधानिक (Statutory) समिति है। अतएव, यात्रा भत्ता नियमावली, 1949 के नियम-144(1) के अधीन समिति के प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य जो उस स्थान के निवासी नहीं है, जहाँ बैठक हो रही है, यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी माने जायेंगे और उन्हें तदनुसार अनुमान्य यात्रा भत्ता एवं विराम भत्ता देय होगा।

सदस्यों को यह यात्रा विराम भत्ता उसी दशा में अनुमान्य होगा जब वे यह प्रमाणित कर देंगे कि उन्होंने किसी दूसरे स्रोत से कोई यात्रा भत्ता या विराम भत्ता नहीं लिया है।

- 5. श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची जो समिति के सचिव-सह-संयोजक हैं, गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
- 6. इसका व्यय आय-व्ययक शीर्षक-2052- सचिवालय सेवाएँ सचिवालय राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों के निमित यात्रा भत्ता के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरुण एक्का, सरकार के सचिव

-----